

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या

/2014

निम्नलिखित के विषय में:

तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14 के अंतर्गत याचिका ।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

विद्युत भवन (8वीं मंजिल), ब्लॉक-डीजे,

सेक्टर-II, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091 (पश्चिम बंगाल)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अनुक्रमणिका पृष्ठ	
2.	शपथ-पत्र	
3.	आवेदनपत्र	
4.	अनुबंध-I : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और	

	शर्ते) विनियमावली, 2014 में यथाविनिर्धारित फार्म-1 से फार्म 16	
	अनुबंध-II : 2014-15 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र के लिए शुल्कों के भुगतान के समर्थन में दिनांक 29.04.2014 का पत्र	
	अनुबंध-III : 2014-19 के दौरान अतिरिक्त व्यय के संबंध में दिनांक 07.07.2014 की निदेशक मंडल की बैठक की एमओएम की प्रति	

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)

मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक :08.2014

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या

/2014

निम्नलिखित के विषय में:

तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14 के अंतर्गत याचिका ।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
विद्युत भवन (8वीं मंजिल), ब्लॉक-डीजे,
सेक्टर-II, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091 (पश्चिम बंगाल)

याचिका का सत्यापन करने के लिए शपथ-पत्र

मैं, ए.के. पांडे, सुपुत्र श्री पी.एन. पांडे, आयु 55 वर्ष, एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत, उपर्युक्त मामले में आवेदक, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और कथन करता हूँ:

1. मैं एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हूँ और उपर्युक्त मामले के तथ्यों से भली भांति परिचित हूँ।
2. इस याचिका में किए गए कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों और/या प्रबंधन के अनुमोदन पर आधारित हैं।

..... अगस्त, 2014 को फरीदाबाद में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और उसमें से कोई सारवान बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शनाख्त की गई

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या

/2014

निम्नलिखित के विषय में:

तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14 के अंतर्गत याचिका ।

और

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

..... याचिकाकर्ता

प्रतिवादीगण :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

विद्युत भवन (8वीं मंजिल), ब्लॉक-डीजे,

सेक्टर-II, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091 (पश्चिम बंगाल)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 के विनियम 7(3) और 14 के अंतर्गत याचिका

सादर निवेदन किया जाता है कि:

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे इसमें आगे 'एनएचपीसी' कहा गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में भारत सरकार की एक कंपनी है। इसके अलावा,

यह, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के अंतर्गत यथापरिभाषित एक 'उत्पादन कंपनी' है।

2. तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन (जिसे इसमें 'टीएलडीपी-III/पावर स्टेशन' कहा गया है) (4X33 = 132 मेगा वाट) कहा गया है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, को 19.05.2013 को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है।
3. एनएचपीसी ने तीस्ता लो डैम-III का निर्माण किया और इसके वाणिज्यिक प्रचालन के आरंभ से इसका प्रचालन तथा अनुरक्षण कर रहा है। इस विद्युत केंद्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति, पश्चिम बंगाल, जो कि परियोजना का मुख्य लाभग्राही राज्य है अर्थात् प्रतिवादी द्वारा यहां उनके साथ हस्ताक्षर किए गए विद्युत खरीद करार (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार, पश्चिम बंगाल में की जा रही है।
4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में, किसी उत्पादन कंपनी द्वारा किसी वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति के लिए समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण का उपबंध है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) के अंतर्गत माननीय आयोग में यह क्षेत्राधिकार निहित है कि वह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या उसके स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों का प्रशुल्क विनियमित करे।
5. याचिकाकर्ता ने प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख अर्थात् 01.04.2013 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) नियमावली, 2009 के विनियम 5 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने, आवेदनपत्र के प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 तथा इनके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार 05.11.2012 को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका संख्या 115/जीटी/2013 दायर की

गई थी। संशोधित याचिका संख्या 115/जीटी/22013 यथास्थिति इसकी वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को पहले ही दायर की जा चुकी है।

6. वर्तमान प्रशुल्क याचिका में विचारित 31.03.2014 को यथास्थिति **182919.45 लाख रुपए** की पूंजीगत लागत संशोधित प्रशुल्क याचिका संख्या 115/जीटी/2013 में पूंजीगत लागत पर आधारित है।
7. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माननीय आयोग ने दिनांक 21.02.2014 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 जारी की है, जो 01.04.2014 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू है।
8. वर्तमान याचिका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में यथाविनिर्धारित प्रशुल्क दाखिल करने के फार्म 1 से 16 में और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण, प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 और इसके तत्पश्चात संशोधन के अनुसार दायर की जा रही है।
9. वर्तमान प्रशुल्क याचिका केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रशुल्क विनियामवली, 2014 के विनियम 7 और 14 के अनुसार तैयार की गई है, जो निम्नलिखित रूप में प्रत्युत्पादित किए जाते हैं:

“7(3) संसूचन प्रणाली या उसके घटक सहित वर्तमान उत्पादन केंद्र या संचरण प्रणाली के मामले में आवेदन, 31.03.2014 तक पहले ही स्वीकार किए गए किसी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो वास्तविक या प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो वास्तविक या प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर) और 2014-15 से 2018-19 तक की प्रशुल्क अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित स्वीकार की गई पूंजीगत लागत के

आधार पर इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से अधिक से अधिक 180 दिन के अंदर किया जाएगा।”

"14. अतिरिक्त पूंजीकरण और विपूंजीकरण:

(1) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात और विच्छेदन तारीख तक, कार्य के मूल दायरे के अंदर निम्नलिखित कारणों से किया गया या किए जाने के लिए प्रक्षेपित नई परियोजना या वर्तमान परियोजना के संबंध में पूंजीगत व्यय विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है:

- (i) किसी भावी तारीख को भुगतानयोग्य होने के लिए मान्यताप्राप्त अनुमोचित देयताएं;
- (ii) निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य;
- (iii) विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार कार्य के मूल दायरे के अंदर आरंभिक पूंजीगत हिस्सों-पुर्जों का प्रापण;
- (iv) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं; और
- (v) किसी वर्तमान कानून का अनुपालन या कानून में परिवर्तन:

बशर्ते कि किसी भावी तारीख को भुगतानयोग्य होने के लिए मान्यताप्राप्त व्यय देयताओं, के आकलनों के साथ-साथ कार्य के मूल दायरे में शामिल किए गए परिसंपत्ति-वार/कार्य-वार निर्माण कार्य और निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य के ब्योरे प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

"14(3) विच्छेदन तारीख के पश्चात निम्नलिखित कारणों से, किया गया या किए जाने के लिए प्रक्षेपित, संसूचन प्रणाली सहित वर्तमान उत्पादन केंद्र या संचरण प्रणाली के संबंध में पूंजीगत व्यय विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है:

- (i) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं;

- (ii) किसी वर्तमान कानून का अनुपालन या कानून में परिवर्तन;
- (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा/आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सांविधिक प्राधिकरणों की समुचित सरकारी एजेंसियों द्वारा दी गई सलाह या निर्देश के अनुसार संयंत्र की सुरक्षा और उच्चतर सुरक्षा की आवश्यकता के कारण किए जाने वाले कोई खर्च;
- (iv) कार्य के मूल दायरे में राख के तालाब या राख हैंडलिंग प्रणाली से संबंधित आस्थगित निर्माण कार्य;
- (v) ऐसी अनुमोचित देयता, पैकेज की कुल अनुमानित लागत के ब्योरों की विवेकपूर्ण जांच के पश्चात विच्छेदन तारीख से पहले निष्पादित किए गए निर्माण कार्य के लिए कोई देयता, इस प्रकार भुगतान रोकने और ऐसे भुगतान जारी करने आदि के कारण;
- (vi) वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसी देयताओं के उन्मोचन करने की सीमा तक विच्छेदन तारीख के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकार की गई निर्माण कार्य की कोई देयता;
- (vii) कोई ऐसा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जो कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों या संचरण प्रणाली, जैसा भी मामला हो, के अलावा उत्पादन केंद्र के दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो। इस दावे की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित तकनीकी औचित्य से की जाएगी जैसे परिसंपत्तियों के नष्टीकरण के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी का अप्रचलन, तकनीकी कारण से क्षमता का उन्नयन जैसे दोष के स्तर में वृद्धि;
- (viii) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मामले में कोई ऐसा व्यय, जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हुई क्षति के कारण (परंतु उत्पादन कंपनी की लापरवाही के कारण माने जा सकने वाले, पावर हाउस के आप्लावन

के कारण न हो) और किसी बीमा योजना से प्राप्त बिक्री की धनराशि का समायोजन करने के पश्चात भू-गर्भीय कारणों से आवश्यक हो गया है और किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया खर्च, जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो।

- (ix) संचरण प्रणाली के मामले में, रिलेज, नियंत्रण और इंस्ट्रुमेंटेशन, कंप्यूटर प्रणाली, पावर लाइन कैरियर संसूचन, डी सी बैटरियां, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन के कारण प्रतिस्थापन, दोष के स्तर में वृद्धि के कारण स्विच यार्ड उपकरण का प्रतिस्थापन, टावर का सशक्तीकरण, संसूचन उपकरण, आपातकालिक पुनर्स्थापन प्रणाली, इंसुलेटर अवसंरचना, पॉलिमर इंसुलेटरों से पोर्सलेन इंसुलेटर का प्रतिस्थापन, बीमा द्वारा कवर न किए गए क्षतिग्रस्त उपकरण का प्रतिस्थापन जैसी मदों पर किया गया कोई अतिरिक्त व्यय और कोई अन्य व्यय, जो संचरण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो; और
- (x) उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में पूर्ण कोयला संबद्धता के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण उत्पन्न ईंधन प्राप्ति प्रणाली में अपेक्षित या किए गए संशोधनों के कारण आवश्यक विवेकपूर्ण जांच के पश्चात न्यायोचित पाया गया कोई पूंजीगत व्यय।

बशर्ते कि विच्छेदन तारीख के पश्चात लिए गए औजारों और साज-सामान, फर्नीचर, एयरकंडीशनरों, वोल्टेज स्टैबिलाइजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, कंप्यूटरों, पंखों, वाशिंग मशीनों, हीट कनवेक्टरों, गद्दों, कालीनों आदि सहित परिसंपत्तियां या लघु मदें प्राप्त करने पर हुए किसी खर्च को 01.04.2014 से प्रशुल्क के निर्धारण के लिए कोई अतिरिक्त पूंजीकरण नहीं माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशन के मामले में ऊपर (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट स्वरूप के व्यय के अलावा, किसी पूंजीगत व्यय की पूर्ति मुआवजा भत्ते से की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी व्यय का दावा पुनरुद्धार; और आधुनिकीकरण (आर एंड एम), ओ एंड एम व्यय के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव तथा मुआवजे भत्ते के अंतर्गत किया गया है तो इस व्यय का दावा इस विनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता।"

10. इस याचिका में विचारित प्रशुल्क वर्षों 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय के ब्योरे अनुबंध-1 के फार्म-9क में दिए गए हैं।
11. केंद्रीय विद्युत विनियमावली आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 पर आधारित, 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए टीएलडीपी-III के संबंध में परिकल्पित वार्षिक निर्धारित प्रभार (एएफसी) निम्नलिखित है: (अनुबंध-I का फार्म-1 देखें)।

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एएफसी	384.95	401.99	409.41	401.85	394.49

12. उपर्युक्त प्रशुल्क प्रस्ताव, उत्पादन केंद्रों से जुड़े और/या संचरण प्रणाली पर होने वाली इसकी संस्थापनाओं में से किसी संस्थापना के संबंध में और/या विद्युत/ऊर्जा की आपूर्ति पर या जल, विद्युत के संचरण, पर्यावरणीय संरक्षण, बिक्री सहित किसी अन्य प्रकार की खपत या अतिरिक्त खपत सहित विद्युत के उत्पादन के संबंध में किसी सरकार (केंद्र या राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित/ लगाए गए किसी अन्य प्रकार के किसी सांविधिक करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, उप-कर को छोड़कर हैं।

13. ऊपर यथाउल्लिखित उपर्युक्त करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों की बाबत किसी भी महीने में संबंधित प्राधिकरणों को एनएचपीसी द्वारा भुगतानयोग्य ऐसे करों/ शुल्कों/ उप-कर /उद्ग्रहणों आदि की धनराशि का वहन और अतिरिक्त रूप से भुगतान प्रतिवादियों द्वारा एनएचपीसी को किया जाएगा और यह उनके द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक क्षमता प्रभारों के अनुपात में प्रतिवादियों द्वारा भुगतानयोग्य होगा।
14. वर्ष 2014-15 के लिए **5,80,000/- रुपए** का याचिका दायर करने का शुल्क, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियमावली, 2012 के अनुसार यूटीआर सं; एसबीआईएन814118294515 के जरिए पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया गया है और दिनांक 29.04.2014 के पत्र के अंतर्गत इसकी सूचना केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को दे दी गई है। पत्र की प्रति **अनुबंध-11** के रूप में संलग्न है।

प्रार्थना

1. 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन का प्रशुल्क, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत और 21.02.2014 को जारी की गई केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 के विनियम 7(3) के अनुसार निर्धारित किया जाए।
2. तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन के वार्षिक निर्धारित प्रभार (एएफसी), **अनुबंध-1** के प्रशुल्क दाखिल करने के **फार्म-1** के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः **389.95 करोड़ रुपए, 401.99 करोड़ रुपए, 409.41 करोड़ रुपए, 401.85 करोड़ रुपए, और 394.49 करोड़ रुपए** परिकल्पित किए गए हैं। इसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में माननीय आयोग द्वारा पहले ही अधिसूचित तरीके से प्रतिवादियों से/को वसूल किए जाने/लौटाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
3. एनएचपीसी को यह अनुमति प्रदान की जाए कि वह ऊपर **पैरा-13** में यथाउल्लिखित उद्ग्रहणों, करों, शुल्कों, उप-कर, प्रभारों, फीस, आदि, यदि कोई है, के लिए प्रतिवादियों को बिल दे।
4. **पैरा-14** में यथाउल्लिखित, यह याचिका दायर करने के शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए।
5. 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क के आवेदन में नोटिसों के प्रकाशन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए।

6. ऐसा अन्य और अगला/अगले आदेश पारित किया जाए/किए जाएं, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)

मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक :08.2014